

की 100/- ₹0 की राशि से अधिक न हो।

उपयुक्त दर पर उल्लिखित जीवन-निर्वाह भत्ते को 20 वर्ष के आधार पर पूँजीकृत किया जायेगा तथा भ-वंचित व्यक्तियों की वितरित करने के लिये संबद्ध राज्य सरकार के पास जमा कर दिया जायेगा।

(ख) सरकार द्वारा पुनर्वास संबंधी रिकार्डों को केन्द्रीयकृत रूप में नहीं रखा जाता है और इस संबंध में सूचना का संग्रहण और उसे एकत्रित करने के मामले में सभी समयावधि तथा प्रयास उन परिणामों के अनुरूप, नहीं होंगे जिस उद्देश्य के लिये यह सूचना मांगी गई है।

(ग) कोयला कम्पनियों द्वारा पुनर्वास कार्य में और त्वरित करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये जाते हैं:—

(i) किसी परियोजना विशिष्ट के संबंध में, जहां तक भूमि अधिग्रहण, विस्थापित व्यक्तियों की विनिर्दिष्ट किये जाने, मुआवजा, आदि की हकदारी का संबंध है, ग्रामिण कार्यवाई की जाती है।

(ii) विभिन्न स्तरों पर आवधिक बैठकें यह देखने के लिये की जाती हैं कि ऐसे व्यक्ति, जोकि विस्थापित

किये गये हैं, उन्हें न्यूनतम कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

(iii) मुआवजा के संबंध में और/अथवा स्थापित नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार रोजगार दिये जाने के संबंध में शीघ्र निर्णय लिया जाता है।

Joint Ventures in Deep Sea Fishing

586. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to set up joint ventures in deep sea fishing in the country's Exclusive Economic Zone (EEZ) during the current financial year;

(b) if so, the details and number of joint ventures projects approved; and

(c) the total investment proposed to be made in these projects?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a)

Yes Sir.

(b) Out of 4 proposals received during 1994-95 one has been approved so far. The details of the cases are furnished in the Statement enclosed. (See below)

(c) The total investment proposed to be made in these project is Rs. 23.5\$ crores.

Statement

Deep Sea Fishing Proposals received during 1994-95

(Rs. In Crores)

| S. No. | Name of the Company | Type of Project | Name of foreign Collaborator | Total Project Cost | Foreign equity |
|--------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Andaman Fisheries, New Delhi | Jt. Venture/Leasing for 3 Stern Trawlers | M/s 2 F (Thailand) Co. Ltd., Bangkok, Thailand. | 1.56 | 0.02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|------|
| 2 | Bay Island Fisheries, Phoni Bay, Port Blair. | Jt. Ventures/Leasing for 2 Stern Trawlers. | M/s Tawakkal Agriculture Ltd., Ramong, Thailand. | 3.45 | 0.02 |
| 3 | Sovin Sea Food (P) Ltd., New Delhi. | Jt. Venture/Leasing for 2 Stern Trawlers. | M/s Valadmir & Olga Ltd., Moscow, Russia. | 15.00 (approved) | 0.08 |
| 4 | Andaman Marine Projects Developments Port Blair. | Jt. Venture/Leasing for 3 Hook & line fishing vessels. | M/s 2 F (Thailand) Co. Ltd., Bangkok, Thailand. | 3.57 | 0.02 |
| | | | | 23.58 | 0.14 |

कोल इंडिया लि० के योजना परिव्यय के अन्तर्गत पूँजीगत व्यय के लिये धनराशि का प्रावधान

* 587. श्री गीपाल सिंह जी० सोलंकी: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना परिव्यय के अन्तर्गत पूँजीगत व्यय के लिये 10,499 करोड़ रुपये की धनराशि देने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो भूमिगत तथा नये खुले मुहाने की शुरू की जाने वाली कोयला खानों सहित खुले मुहाने की खानों के विकास का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कोकिंग कोल प्राप्त करने के लिये भूमिगत खानों का विकास करने के संबंध में सुझाव आमंत्रित किये गये हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोल इंडिया लि० ने जितनी योजनाओं को अंतिम रूप दिया है उनका ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार यादव) (क) योजना आयोग ने आठवीं योजनावधि के लिये कोल इंडिया लि० के संबंध में (1991-92 कीमतों पर) 8520 करोड़ रुपये की राशि के परिव्यय की सिफारिश की है।

(ख) कुल परिव्यय में से 7122 करोड़ रुपये की राशि खनन परियोजनाओं पर खर्च किये जाने का प्रस्ताव है। इसमें से भूमिगत खानों तथा ओपेनकास्ट खानों का हिस्सा क्रमशः लगभग 28% तथा 72% है। योजना आयोग द्वारा आठवीं योजना के अंतिम वर्ष तक ओपेनकास्ट तथा भूमिगत खानों से कोयले का उत्पादन क्रमशः 196.15 मिलियन टन तथा 73.85 मिलियन टन किये जाने की सिफारिश की गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि० को कोककर कोयले के उत्पादन में वृद्धि किये जाने के लिये नई भूमिगत खानों को विकसित किये जाने के मामले में प्राथमिकता दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। तदनुसार च.लू. परियोजनाओं के अलावा 22 कोयला खानें भूमिगत तथा ओपेनकास्ट—दोनों ही तरह की खानों को कोककर कोयले के उत्पादन